विचार बिन्दु

अगर तुम गलतियों को रोकने के लिए दरवाजे बंद कर दोगे तो सत्य भी बाहर आ जायेगा। -टैगोर

केजरीवाल की महत्वाकांक्षा "आप" को ले डूबी

अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन दिल्ली में प्रारंभ किया गया और वे भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए जन लोकपाल बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे। इस आंदोलन को जिस प्रकार से अपार और ऐतिहासिक समर्थन मिला, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता भ्रष्टाचार से कितनी त्रस्त है। इस आंदोलन को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखा गया। यहां तक कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अन्ना हजारे के मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। इस आंदोलन को सभी मीडिया चैनलों में कई दिनों तक लगातार टीवी पर दिखाया गया। इसका प्रभाव यहां तक रहा कि भारतीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और अंततः जन लोकपाल बिल पारित किया गया।

इस आंदोलन को चलाने वालों ने 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' नाम से एक संस्था बनाई जिसमें कई प्रमुख सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनमें एक प्रमुख व्यक्ति अरविंद केजरीवाल थे जो भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी थे किंतु उन्होंने सरकार की नौकरी छोड़कर एक एन जी ओ 'परिवर्तन' के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को जागृत करने का काम किया।

अन्ना हजारे के आंदोलन में देश की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं जिनमें पूर्व जज, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, वकील के साथ ही कई सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस आंदोलन की समाप्ति के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ अपने साथियों के साथ एक राजनीतिक दल 'आम आदमी पार्टी' की स्थापना की। यह निर्णय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समय लिए गए उस निर्णय के विरुद्ध था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि आंदोलनकर्ता कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे।

जब आम आदमी पार्टी को बनाया गया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह सामान्य सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं अपितु उनका उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन करना है। उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों के कई स्वैच्छिक कार्यकर्ता और प्रमुख व्यक्ति जुड़े, जिनमें नौसेना के पूर्व सेनाध्यक्ष एडमिरल रामदास, किरण बेदी, न्यायाधीश तेवतिया, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, पत्रकार आशुतोष, चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव, पत्रकार शाज़िया इल्मी, मेधा पाटकर, कुमार विश्वास जैसे हजारों लोग शामिल थे।

आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव 2013 में दिल्ली विधानसभा का लड़ा। पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें प्राप्त हुई और उसने कांग्रेस के सहयोग से सरकार का गठन किया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 49 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और यह कहा कि वे जनता के पास जाकर उनकी सहमति से उम्मीदवार तय करेंगे।

2015 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक और अद्भुत सफलता प्राप्त करते हुए विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतीं। जीतने वाले विधायकों में अधिकांश अत्यंत ही साधारण कार्यकर्ता थे। आम आदमी पार्टी की सफलता में युवाओं का बड़ा योगदान था जो केजरीवाल की आदर्श बातों से प्रभावित होकर आप में शामिल हुए। कई युवा तकनीकी विशेषज्ञों ने तो विदेशों से दिल्ली आकर 'आप' के लिए प्रचार किया । एक बार ऐसा लगने लगा था कि भारत के परिदृश्य में एक स्वच्छ राजनीति के अध्याय का प्रारंभ हुआ है ।

यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त न होने के कारण सरकार सभी मामलों में पूर्ण अधिकार युक्त नहीं थी।कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी निर्णय केंद्र सरकार के पास थे। दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों पर भी दिल्ली सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। आप सरकार ने सबसे पहले बिजली और पानी एक सीमा तक निःशुल्क कर दिए। साथ ही सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से भी बहुत सुधार किए, जिन्हें बहुत सराहना मिली।

सरकार की लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार के कार्य में कई प्रकार से बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का नियंत्रण राज्य सरकार से ले लिया । केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और उप राज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम काज में बाधा उत्पन्न करने लगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई सारे विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गए। दिल्ली सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों पर नियंत्रण संबंधी प्रकरण में सफलता भी मिली, किंतु इसको केंद्र सरकार ने संसद से कानून में संशोधन करके प्रभावहीन कर दिया।

इसी बीच कई प्रमुख व्यक्तियों ने धीरे-धीरे अरविंद केजरीवाल की तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। इनमें प्रमुख थे प्रशांत भूषण, गोपीनाथ, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, शाजिया इलमी, कपिल मिश्रा, आशुतोष, कुमार विश्वास आदि । कुछ ने भाजपा की सदस्यता ले ली। इन सब के द्वारा आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाने का प्रमुख कारण केजरीवाल का तानाशाही रवैया और पार्टी के अपने मूल सिद्धांतों से भटकना था।

जिस व्यक्ति ने सरल सादा जीवन जीने की सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा की हो वह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाए और अपने लिए शीश महल बनवा ले तो उसे दोगला ही कहा जाएगा। केजरीवाल का अपने लिए शीश महल बनवाना उनके लिए ताबूत में आखिरी कील की तरह सिद्ध हुआ और उसका पूरा लाभ भाजपा की चुनावी मशीनरी ने उठाया।

इन सबके बावजूद 2020 के चुनाव में आपको 70 में से 62 सीटों पर फिर विजय प्राप्त हुई। यह उल्लेखनीय है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की। अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा कि वे अपने अकेले के बलबूते पर आप को जिता सकते हैं। उनमें एक प्रकार से अहंकार आ गया। वे सार्वजनिक तौर पर भले ही बार-बार यह कहते रहे कि वे एकदम साधारण व्यक्ति हैं और उनकी कोई औकात नहीं है किंतु उनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल इसके विपरीत था। धीरे-धीरे आम आदमी पार्टी पूरी तरह केजरीवाल - केंद्रित हो कर रह गई।

भारत सरकार ने केजरीवाल सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा कर उन्हें जेल में डाल दिया। एक समय ऐसा था जब लगभग एक तिहाई विधायकों पर कोई न कोई अपराधिक कार्यवाही दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही थी। इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों पर पूरा ध्यान दिया और कुछ समय में एक ऐसी छवि बना ली कि दिल्ली के सरकारी स्कूल निजी विद्यालय से भी कहीं बेहतर हैं। यह सही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप की सरकार ने अच्छा काम किया ।

एक और जहां केंद्र की भाजपा सरकार के उपराज्यपाल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए परेशानियां उत्पन्न करते रहे, वहीं केजरीवाल भी अपने रास्ते से धीरे-धीरे भटकते चले गए। उन पर शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगे जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इसी आरोप में उनके उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा। इसी दौरान 'आप' को पंजाब के चुनाव में अच्छी सफलता मिली और वहां उन्होंने 2022 में अपनी सरकार बनाई । आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता भी मिल गई।

इन सब सफलताओं के कारण अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा कि वे पार्टी से बड़े हो गए हैं। यह सोच ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पतन का कारण बनी। जो व्यक्ति जन आंदोलन से निकला हो वह अपने सहयोगियों को, जो अपने-अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, को सम्मान के साथ अपनी पार्टी में बनाए नहीं रख सके, वह सही मायने में जन नेता कहलाने योग्य नहीं हो सकता ।

जिन साथियों को अरविंद केजरीवाल ने अपमानित करके पार्टी से निष्कासित किया उनमें प्रशांत भूषण जैसे प्रतिष्ठित वकील भी थे जिन्होंने लगातार सदैव भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने जंग जारी रखी और वंचित - प्रताड़ितों के पक्ष में सदैव न्यायालय में लड़ते रहे। इसी प्रकार योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, आशुतोष और कुमार विश्वास को अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ने ही पार्टी से दूर किया । अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ जिस प्रकार अशोभनीय व्यवहार किया उसने भी उनकी तानाशाही प्रवृत्ति को ही स्थापित किया।

8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के जो परिणाम आए हैं, उनमें आम आदमी पार्टी को कुल 20 सीटें ही प्राप्त हुईं और वह सत्ता से बाहर हो गई है, हालांकि इसका वोट प्रतिशत भाजपा से केवल 1.5 प्रतिशत ही कम है।

आम आदमी पार्टी का जो हश्र हुआ है, उससे सभी नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि यदि वह स्वयं को दल से बड़ा समझें एवं लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो फिर वह शीघ्र ही इतिहास का भाग हो जाते हैं। जिस आम आदमी पार्टी को जनता ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम का प्रतीक मान लिया था, वही अपने अपने नेता के स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और महत्वाकांक्षा के कारण उससे दूर हो गई है।

यह अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ही थी कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का भाग होने के बावजूद, हरियाणा में अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसके कारण कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। इसी का बदला कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े करके ले लिया। यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े होते तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बन चुकी होती क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोटो में अंतर लगभग 2.2 प्रतिशत का ही था।

जिस व्यक्ति ने सरल सादा जीवन जीने की सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा की हो वह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाए और अपने लिए शीश महल बनवा ले तो उसे दोगला ही कहा जाएगा। केजरीवाल का अपने लिए शीश महल बनवाना उनके लिए ताबूत में आखिरी कील की तरह सिद्ध हुआ और उसका पूरा लाभ भाजपा की चुनावी मशीनरी ने उठाया।

देश के लिए तो यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस व्यक्ति और दल को सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पर्याय मानते हुए जनता ने सर माथे बिठाया था उसी ने विश्वासघात करते हुए एक सामान्य राजनीतिक की तरह वही सब किया, जिसके विरुद्ध वह लड़े।

एक नागरिक तो यह अपेक्षा ही कर सकता है कि भविष्य में ऐसे सच्चे नेता उसका नेतृत्व करने के लिए मिलें जो इमानदारी के साथ जनहित में नैतिक साहस जुटा कार्य करते रहें। ऐसा करके वे चुनाव भले ही न जीते पाएं, किंतु जनता के दिलों पर सदैव राज करेंगे । फिलहाल तो हम एक ही वाक्य में पूरा सारांश लिख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अत्यधिक महत्वाकांक्षा ही आम आदमी पार्टी के पतन का मुख्य कारण बनी।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

केंद्रीय आम बजट-2025: कृषि क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टि

राम शर्मा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से हाल ही पेश किए गए भारतीय बजट 2025-26 ने कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करना और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना है। कृषि क्षेत्र में भारत के लगभग 60 प्रतिशत लोग रोजगाररत हैं। इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 18-20 प्रतिशत का योगदान है। वर्ष 2025-26 का बजट जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच किसानों की आय दोगुनी करने, उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.75 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान और विकास, और किसान कल्याण योजनाओं के लिए धन शामिल है। बढ़े हुए आवंटन से सरकार का कृषि को अधिक लाभदायक और स्थिर बनाने पर जोर स्पष्ट होता है।

जलवायु परिवर्तन के कृषि पर बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बजट में "कृषि विकास योजना - जलवायु-सहिष्णु कृषि" नामक एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सूखे से प्रभावित होने वाली फसलों, कुशल जल प्रबंधन और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। किसानों को सटीक खेती, ड्रिप सिंचाई और वानिकी जैसी जलवायु-अनुकूल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसी प्रकार किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास बजट में किया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता देने संबंधी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों और किराएदार किसानों को शामिल किया गया है। इस कदम से तीन करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिए वित्तीय समावेशन और स्थिरता सुनिश्चित होगी।

बजट में राष्ट्रीय कृषि डिजिटल मिशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य खेती में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है। इसमें फसल निगरानी, मिट्टी स्वास्थ्य मूल्यांकन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग शामिल है। सरकार ने किसानों के उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने और उनकी बारगेनिंग पावर बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों से लैस 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करने की भी योजना बनाई है।

इसी प्रकार कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई थी। इसे सुदृढ करते हुए बजट में इसका कोष 1 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। इस कोष का उपयोग कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों के विकास के लिए किया जाएगा, ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और किसानों की आय में सुधार हो सके। इसके अलावा, सरकार ने क्षेत्रीय विशेषज्ञता और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 500 नए कृषि-क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई है।

सतत कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए, बजट में 'भारत ऑर्गेनिक्स' नामक एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 2,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस पहल के तहत किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती पद्धतियों में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें रासायनिक इनपुट को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय जैविक प्रमाणन प्राधिकरण बनाने की भी योजना बनाई है।

सहायक क्षेत्रों की क्षमता को पहचानते हुए, बजट में मत्स्य पालन और पशुपालन के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें जलीय कृषि और समुद्री कृषि को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन 2.0 की स्थापना और पशुधन उत्पादकता और रोग नियंत्रण में सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन का विस्तार शामिल है।

बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए आवंटन बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे कृषि के मंद मौसम में ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। इसके अलावा, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उद्यिमता और कृषि-व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षित करने के लिए एक नया किसानों के लिए कौशल विकास मिशन शुरू किया गया है।

किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, बजट में कृषि गतिविधियों में लगे सहकारी समितियों के लिए कर छूट की घोषणा की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी योजना को बढ़ाया गया है, और प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया है। बजट में बाजार संपर्क को मजबूत करने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया गया है। ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म को अधिक वस्तुओं और बाजारों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने मसालों, फलों और जैविक उत्पादों जैसे उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

भारतीय बजट 2025-26 कृषि क्षेत्र के लिए एक आशाजनक दृष्टि प्रस्तुत करता है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना, धन का समय पर वितरण सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना इनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को खंडित भूमि जोत, ऋण तक अपर्याप्त पहुंच और वैश्विक बाजार उतार-चढ़ाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

सरकार का प्रौद्योगिकी, स्थिरता और किसान कल्याण पर ध्यान सही दिशा में एक कदम है। हालांकि, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा। इन पहलों की सफलता अंततः किसानों को सशक्त बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और एक लचीला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय बजट 2025 कृषि क्षेत्र के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जलवायु सहनशीलता, प्रौद्योगिकी अपनाने और किसान कल्याण को प्राथमिकता देकर, सरकार ने एक अधिक समृद्ध और स्थायी भविष्य की नींव रखी है। जैसे-जैसे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र समावेशी विकास को गति देने और इसके 1.4 अरब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बजट का समठा दृष्टिकोण किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ और उन्हें दूर करने की एक स्पष्ट दृष्टि को दर्शाता है, जो भारतीय कृषि में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करता है।

-राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

शहद की मिठास ने बदल दी तकदीर, मधुमक्खी पालक अमरसिंह बना उद्योगपति

- **देश-विदेश में शहद कारोबार से बनाई पहचान, 12 हजार की पूंजी से बना करोड़पति**
- **अमर सिंह प्रतिवर्ष करीब 4.5 से 5 करोड़ रूपए का शहद बेच रहे हैं और कई राज्यों में मधुमक्खी पालन की 100 से अधिक यूनिट स्थापित की है**

हलैना, (निसं)। जब व्यक्ति मन में कुछ करने की ठान ले और रास्ता में आने वाली दिक्कतों का सामना कर ले, उसे दुनियां की कोई भी कठिनाईयां नहीं रूकावट नही डाल सकती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सफलता हासिल करता है और प्रत्येक क्षेत्र में आसमां छु लेता है। ऐसा व्यक्ति है भुसावर उपखंड क्षेत्र के नैवाडा गांव की धरा में जन्मे साधारण किसान रत्तीराम सिंह के पुत्र अमर सिंह। जिसने समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता से मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण संयंत्र लगाने की प्रेरणा लेकर साल 1998 में नैवाडा गांव में मधुमक्खी के मात्र चार डिब्बे से मधुमक्खी पालन की शुरूआत की।

जीवन में कई कठिनाईयां आई, लेकिन इन्हें निदेशक सीताराम गुप्ता ने हर समय मदद दी और हिम्मत बंधाई। आज अमर सिंह की शहद की मिठास ने तकदीर बदल डाली, जो मधुमक्खी पालक से शहद कारोबार का उद्योगपति बन गया, जिसकी मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण व उत्पादन में देश-विदेश में पहचान बन गई। साल 1998 में मात्र 12 हजार की लागत से आज दस करोड़ का कारोबारी बन गया, जो प्रतिवर्ष करीब 4.5 से 5 करोड़ रूपए का शहद बेच रहे हैं और कई राज्यों में मधुमक्खी पालन की 100 से अधिक यूनिट स्थापित कर हजारों बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बना दिया। किसान रत्तीराम सिंह के पुत्र अमर सिंह कई बार राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं।

अमर सिंह ने बताया कि समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने साल 1998 में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिलाकर मात्र मधुमक्खी के चार डिब्बे उपलब्ध कराए और मधुमक्खी पालन के साथ-साथ शहद प्रसंस्करण संयन्त्र लगाने की सलाह दी। आज मेरे पास 3 हजार 500 से अधिक मधुमक्खी के डिब्बे हैं और देश के कई राज्यों में 100 से अधिक मधुमक्खी पालन की यूनिट स्थापित करा दी है। साथ ही नैवाडा गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र लगाकर स्वयं का उद्योग स्थापित कर लिया। प्रतिदिन 3 से 5 टन शहद प्रसंस्करण कर प्रतिवर्ष साढे चार से पांच करोड़ का शहद बेच दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मधुमक्खी पालन व शहद प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की है, जिससे मधुमक्खीपालकों सहित शहद कारोबार से जुड़े व्यापारी आदि को लाभ मिलेगा। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। देश-विदेश में आज भरतपुर जिले की पहचान सरसों पैदावार के साथ-साथ शहद उत्पादन में कायम है। उन्होंने बताया कि सरकार की मदद से अब मधुमक्खीपालन और शहद उत्पादन में आए दिन प्रगति होने लगी हैं।

उन्होंने बताया कि निदेशक सीताराम गुप्ता का मार्गदर्शक सार्थक रहा, जो भी ये देन है, वह गुप्ता जी की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भरतपुर में हनी टेस्टिंग लैब एण्ड रीजनल बी कीपिंग रिसर्च सेन्टर स्वीकृत कर दिया, जिसको भूमि भी आवंटित हो चुकी है और जल्द ही ये सेन्टर स्थापित हो जाएगा, जिससे हनी कारोबार में बढोतरी होगी।

समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने बताया कि साल 1998 में भरतपुर जिले के बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खीपालन का प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसमें नैवाडा गांव निवासी अमर सिंह पुत्र रत्तीराम भी शामिल था, जिन्हें चार डिब्बे मधुमक्खी के उपलब्ध कराए, जो प्रारम्भ में कई बार हताश हो गया, लेकिन उसे इस कार्य को प्रगति देने के लिए हिम्मत बंधाई और मधुमक्खीपालन के साथ-साथ शहद प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के सलाह दी और देश के कई प्रसंस्करण संयंत्र मालिकों से सम्पर्क कराया। जब अमर सिंह को पता चला कि मधुमक्खी पालन से अधिक आय शहद प्रसंस्करण में होती है, जिसने गांव में ही शहद प्रसंस्करण संयंत्र लगा डाला और आज ये शहद प्रसंस्करण से जुड़ी हस्तियों में शामिल हो गया।

प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को नए सेशन से पहले 4242 प्रिंसिपल मिलेंगे

- **काउंसलिंग से पहले शिक्षा विभाग ने स्थायी सीनियरिटी लिस्ट जारी की**

बीकानेर, (निसं)। प्रदेशभर के सरकारी सीनियर सैकंडरी स्कूल को नए सेशन से पहले प्रिंसिपल मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने साल 2023 तक की पदोन्नति के बाद काउंसलिंग के लिए सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके आधार पर नए प्रमोटेड प्रिंसिपल पोस्टिंग के लिए अपनी वरीयता दे सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सीनियरिटी लिस्ट में चयनित 4242 प्रिंसिपल को अलग-अलग वरीयता नंबर दिए गए हैं। अब काउंसलिंग में ये टीचर इसी आधार पर वरीयता भी दे सकेंगे। वरीयता के आधार पर ही पोस्टिंग के लिए पहले स्थान दिया जाएगा। राज्य स्तर पर बनी इस सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर जिलों में पोस्टिंग होगी। वरीयता में प्रिंसिपल भले ही एक नंबर पर हो, लेकिन वो अपने जिले के स्कूल का ही चयन करता है। ऐसे में जिला स्तर पर अपनी वरीयता के आधार पर प्रिंसिपल को पसंदीदा स्कूल मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सभी प्रिंसिपल को उनके पूर्व पद पद पर ही कार्यभार ग्रहण का आदेश दिया गया है। नए सिरे से काउंसलिंग होने के बाद इन्हें नए पदस्थापन आदेश मिल सकते हैं। काउंसलिंग के दौरान स्कूल के नाम सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, उन्हीं का चयन किया जा सकेगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी स्कूल ओपन नहीं होंगे। जिन स्कूल में विभाग को पहले प्रिंसिपल भेजने हैं, उन्हें ही ओपन किया जा सकेगा। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि विभाग सभी स्कूल ओपन नहीं करता है, जिससे टॉप वरीयता के बाद भी टीचर को अपने नजदीकी स्कूल नहीं मिल पाते।

राशिफल मंगलवार 11 फरवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, पुष्य नक्षत्र सायं 6:34 तक, आयुष्मान योग प्रातः 9:06 तक, वणिज करण सायं 6:56 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मिथुन, बुध-मकर, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग सायं 6:34 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सायं 6:34 से सूर्योदय तक है। भद्रा सायं 6:56 से आरम्भ होगी। आज बुध कुम्भ में दिन 12:32 पर प्रवेश करेगा। आज ललिता जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:56 से 11:18 तक, लाभ-अमृत 11:18 से 2:04 तक, शुभ 3:26 से 4:49 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:10, सूर्यास्त 6:12

मेष

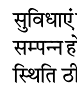

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

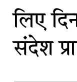

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन

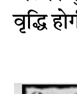

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

कर्क

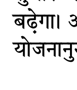

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

सिंह

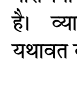

नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी।

कन्या

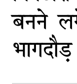

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

तुला

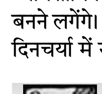

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। दिनचर्या में सुधार होगा।

वृश्चिक

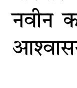

परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

धनु

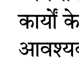

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मकर

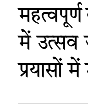

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

कुंभ

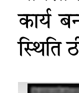

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

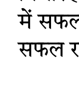

परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।